possessing drugs in commercial quantities is quite severe. It is rigorous imprisonment often years and huge fines. Enforcement is a matter that is now in the hands of several agencies essentially State agencies and I admit that enforcement is perhaps not as strict as it should be. But all I can say is, yes we must improve the machinery as well as its enforcement and visit drug peddlers, especially those who peddle drugs to our children, with the severest penalty. But our courts must also respond to the mood of Parliament, to the mood of law makers. The special courts and the High Court must also recognise that the drug peddling and drug trafficking is a grave menace to the society, and if they find the person guilty, they must visit them with the severest penalty. I would support severe penalty when a person is found guilty.

Acquisition of new planes for Air India and Indian Airlines

*385. SHRI SHARAD YADAV:† PROF. R.B.S. VARMA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have finally decided to buy new planes for Air India/Indian Airlines;

(b) if so, the details thereof and the names of companies which have been short listed for acquisition of planes for both the airlines;

(c) by when the orders would be placed with the manufacturing companies and planes delivered to the airlines; and

(d) what is the total amount of expenditure involved in these deals and the present status of the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Regarding acquisition of new plans for Air India and Indian Airlines (a) to (d) In so far as Indian Airlines is concerned, Cabinet Committee

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sharad Yadav.

on Economic Affairs in its meeting held on 25.08.2005 had approved the proposal of acquisition of 43 aircraft comprising 19 A-319,4 A-320 and 20 A-321 from Airbus Industries at a total cost of Rs. 7838 Crores. Government has accorded approval to the project on 29.09.2005. Delivery of the aircraft would commence in October 2006.

As regards, acquisition of Aircraft by Air India and Air India Charters Limited, a subsidiary of Air India, the Public Investment Board (PIB) in its meeting held on 13th October, 2005, had approved the proposal for acquisition of 50 aircraft viz. 8XB777-200LR, 15XB-777-ER and 27XB-787-8 by Air India at an estimated cost of Rs. 33197.47 Crores and 18XB737-800 aircraft at an estimated cost of Rs. 4,952 Crores. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has also accorded "in principle" approval to the acquisition subject to the final round of negotiations by an EGOM.

श्री शरद यादवः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिए नए जहाज लेने का फैसला हुआ, तो कितने जहाज दोनों एयरलाइन्स के लिए खरीदे जा रहे हैं? कितना अमाउंट उसमें है और जो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, उसकी प्रगति क्या है और कहां तक आप पहुंचे हैं?

श्री प्रफुल्ल पटेलः माननीय सभापति जी, आदरणीय शरद यादव जी पहले इसी मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, इसलिए मैं बड़ी इज्जत के साथ उनको कहना चाहूंगा....

श्री सभापतिः सावधान होकर जवाब देना।

श्री प्रफुल्ल पटेलः वैसे हमारा जबलपुर और गोन्दिया का नजदीक का रिश्ता है...

श्री सभापतिः रिश्ता यहां नहीं चलेगा।

श्री प्रपुल्ल पटेलः सर, इसमें थोड़ा संशोधन करने की अनुमति मैं चाहूंगा कि यह जो हमने लिखित उत्तर दिया है, उसमें आंकड़ा दिया है, वह इंडियन एयरलाइन्स के लिए 10,237 करोड़ रुपये का है, लेकिन इसके पश्चात ही EGOM में कटौती होकर यह आंकड़ा करीब 9,888 करोड़ है, वह माना जाए। लिखित उत्तर में जो दिया गया है, आपकी आज्ञा से मैं पहले उसको करेक्ट कर देता हूं।

जहां तक हवाई जहाज खरीदने का प्रश्न है, करीब 15-16 वर्षों से जो हवाई जहाज खरीदने का सिलसिला था और विशेषकर पब्लिक सेक्टर के लिए थमा हुआ था। मुझे आप सबके समक्ष यह रखते हुए खुशी होती है कि इंडियान एयरलाइंस के जहाज खरीदने का सिलसिला करीब करीब समाप्त हो गया है। इंडियन एयलाइंस के लिए 43 हवाई जहाज, एयरबस-ए-319, ए-320 और ए 321 है। इसमें ए-319 की संख्या 19 है और ए-320 चार है और ए-321 बीस है। इस प्रकार से 43 हवाई जहाज खरीदने का विचार है और इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजरते हुए CCEA और CCEA के पश्चात, क्योंकि हमको यह लगा कि हम इसमें और अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए Empowered Group of Ministers बनाया गया था। माननीय चिदम्बरम साहब यहां बैठे हुए हैं, ये उसके अध्यक्ष थे। उसके पश्चात करीब 350 करोड़ की और कटौती करके, मैं जिस आंकड़े में संशोधन कर रहा था, उसमें जरा गलती हो गई थी, यह 9888 करोड़ के एप्रोक्सीमेट इस कीमत में 43 जहाज खरीदने का letter of indent भी साइन हो चुका है। जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, एयर इंडिया में करीब 68 जहाज लेने का निर्णय हुआ है और इसके लिए Cabinet Committee on Economic Affairs की भी इन प्रिसिंपल मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। उसमें भी एक CCEA ने EGOM बनाने का निर्णय लिया है। उस EGOM के माध्यम से मैन्युफैक्रस के साथ चर्चा होगी और चर्चा करके जितनी भी उसमें कीमत घटाई जा सकती है, उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। पिछली गुरूवार को ही CCEA में यह इन प्रिसिंपल मंजूरी मिली है। यह 68 जहाज का कॉम्बीनेशन है, Boeing 777-200 long range, जो इंडिया से US या ऐसे लांग डिसटेंस नान स्टाप जा सकते हैं। 15 है,Boeing 777-ER और 27 हैं,Boeing787 और इसकी अंदाजन कीमत करीब 33,197 करोड़ है। हम चर्चा में या निगोसिएशन में जो भी कम कर पाएंगे, उसकी पूरी कोशिश होगी। उसके पश्चात् ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। यह Boeing 737-800 अच्छा हवाई जहाज है, करीब 4952 के अंदाजन की कीमत पर ले जाने का एक इन प्रिंसिपल फैसला हुआ है।

श्री शरद यादवः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इंडियन एयरलइंस का नौ हजार करोड़ या दस करोड है और एयर इंडिया का 23 करोड़ है, मेरा उसके एमाउंट पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो आप कहेंगे वह ठीक है। 9-11 के बाद दुनिया के जहाज बहुत खाली हो गए थे। हमारे देश में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं कि पर यदि जहाज लिए जाते तो 9-11 के बाद इतने जहाज खाली हो गए थे कि यहां पर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और यहां जो टेक्नीशियन्स हैं, उनकी संख्या भी पर्याप्त है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा एमाउंट और इसके बाद निश्चित तौर पर आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहूंगा कि इस खरीद के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसको मैं इस समय बयान नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस के जो

एम.डी. थे उन्होंने एक पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि यह जो खरीद है और जो इसकी प्रक्रिया है, इनके सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और मैं जानता हूं कि वे एक ईमानदार आफिसर थे। वे यहां से बदल दिए गए। यह जरूरत नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बीच में शुरू हो जाते हैं।

श्री शरद यादवः सभापति जी, पहले देश के सवाल के बारे में थोड़ी देर सुन लीजिए। मेरा निश्चित तौर पर यह निवेदन है कि इतनी बड़ी खरीद हो रही और इतने बड़े जहाजों की संख्या बढ़ाने का है, जब कि प्राइवेट एयरलाइंस बड़े पैमाने पर आ रही है और आप प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का बहुत जिक्र कर रहे हैं, क्या जरूरत है इस देश के एक्सचैकर से इतने बड़े पैमाने पर खर्च करने का, क्या Wet Lease पर जहाज लिए जा सकते हैं?

श्री सभापतिः ठीक है, ठीक है।

श्री शरद यादवः मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस नीति को बन्द कर इस काम को करने का काम करेगी?

श्री प्रफुल्ल पटेलः मुझे लगता है कि आदरणीय शरद यादव जी तो स्वंय इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की आज जो परिस्थिति है, शायद यह निर्णय अगर आपने अपने समय में लिया होता, तो आज यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। मैं यह भी कहना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी के पश्चात् 16 साल तक कोई हवाई जहाज लेने का जो निर्णय नहीं लिया गया, पारदर्शिता के साथ वह निर्णय लेने के काम इस सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, अगर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की हमें इतनी जरूरत महसूस नहीं होती है, तो फिर हम लोगों को यह निर्णय लेना चाहिए कि आगे हम लोगों को इस देश का सिविल ऐविएशन क्षेत्र किस दिशा में ले जाना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः आदरणीय सभापति जी, मैंने यह निवेदन किया है कि वेट लीज पर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)... इन्हें बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेलः मुझे जवाब देना है ...(**व्यवधान**)... मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादवः मैंने जो बात कही है, उन्हें उसका जवाब देना चाहिए, ...(**व्यवधान**)... बड़ा जबर्दस्त फैसला किया है, आ गया है समय, पता चलेगा ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेलः शरद यादव जी, मुझे जवाब देने दीजिए न। जब आप मंत्री थे, उस वक्त 9/11 के पश्चात् आप ही थे ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः नहीं, नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेलः मतलब आपके सहयोगी थे ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः यह ठीक है।

श्री प्रफुल्ल पटेलः और जब से यह सरकार आई है, इस सरकार ने पहले दिन से यह फैसला लिया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मजबूत करना है। अगर निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस पीछे गई है, तो वह सिर्फ दो कारणों से गई है। एक तो हमने उनको नए हवाई जहाज खरीद कर नहीं दिए और दूसरा यह कि आप जो कह रहे हैं कि हमने उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। जब से हम आए हैं, हमने लीज पर हवाई जहाज लेने का सिलसिला लगातार जारी रखा, लेकिन आज जितनी मात्रा में चाहिए, आज विश्व में कहीं भी टेंडर निकालें गए हैं, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के, तो भी हम उस मात्रा में हवाई जहाज प्राप्त नहीं कर सके। यह सच्चाई है, वास्तविकता है, यह हमारे रेकार्ड कहते हैं। लेकिन जहां तक आप कोई और बात कहते हैं, हमने पारदर्शिता में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। मैं आपको एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पहली बार इस देश की कोई भी बड़ी खरीदी के इतिहास में हमने इसमें एक लेयर डालने की कोशिश की, एक सी.जी. सुमैय्या, फार्मर सीएजी/फार्मर सीवीसी की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में जो सारी प्रक्रिया है, उसकी जांच की, उसमें कीमतों के बारे में चर्चा की, नेगोसिएशन किया और उसके पश्चात् सीसीए की मंजूरी मिलने के बाद भी ईजीओएम बनाकर उसकी कीमतों को और घटाने का काम किया है। मैं नहीं समझता हूं कि इससे ज्यादा पारदर्शिता हम या कोई और भी कर सके।

श्री शरद यादवः सभापति जी, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहूंगा, ...(**व्यवधान**)... मैंने जो सवाल पूछा है ...(**व्यवधान**)... उन्होंने तो अपने काम के बारे में तो कह दिया ...(**व्यवधान**)... मैंने सवाल पूछा है कि इसमें जो वेट लीज का ऑस्पेक्ट है ...(**व्यवधान**)... वेट लीज का आस्पेक्ट है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप क्या कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेलः शरद यादव जी, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि यह वेट लीज नहीं, आप जो कहना चाहते हैं, आप उसे ड्राई लीज कहना चाहते हैं, क्योंकि वेट लीज और ड्राई लीज में फर्क है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे कोई वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)... आप जो कहना चाहते हैं, वह ड्राई लीज की बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सर, मैं वेट लीज ही कह रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेलः यह वेट लीज का सवाल नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप ड्राई लीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं अपनी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं।

प्रो. रामबख्श सिंह वर्माः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध में अपना पूरक प्रश्न रखना चाहता हूं। मेरे पूरक प्रश्न के दो भाग हैं। उसका "अ" भाग यह है कि आपकी दोनों कंपनियों के द्वारा जो 111 विमानों के क्रय करने की बात है, उसमें लगभग 48 हजार करोड़ रुपये लगेंगे। आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि 48 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे है? यह "अ" भाग है।

श्री सभापतिः आप एक ही क्वेश्न कर लीजिए। 48 हजार करोड़ कोई मामूली बात थोड़ा ही है, उसकी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, बताइये।

श्री प्रफुल्ल पटेलः माननीय सभापति जी, मैं आपको और पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं एअर-इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स सरकारी कंपनियां जरूर है, जो सरकार के निर्देश सरकार की जिम्मेदारी और सरकार के दायित्व को निभाने का काम पूरा करती हैं। सरकार ने इन दोनों कंपनियों को जो इक्विटी सपोर्ट शुरू में दिया है, वह मात्र 107 करोड़ और 157 करोड़ है, इसके अलावा कोई बजटरी सपोर्ट एकर-इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स को नहीं दिया है। सवाल यह है कि किसी प्रकार से यह 48 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा लाए हैं, या जो भी कीमत आपने कही है, मैं आंकड़ा पूरा नहीं कहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

प्रो.रामबख्श सिंह वर्माः आपने बताया है, 48 हजार करोड़ रुपए।

श्री प्रफुल्ल पटेलः सुनिए, तो। क्योंकि ये अपनी कंपनियां है, सरकार इनको सपोर्ट करना चाहती है और इसलिए सोवरन गांरटी भी इस परचेज के लिए सरकार ने देने का फैसला किया है। इसके अलावा ये कंपनीज मार्केट बोरोइंग से अपने एअरक्राफ्ट एक्वलीजिशन का काम पूरा करेंगी।

और आपने ही मुनाफे से अपने इंटरनल एक्रूवल से इस पैसे को लौटाने का काम भी करेंगी। इसलिए सरकार को इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आज तक सरकार ने जब जब एअर-इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स को गारंटी दी है, इन कंपनियों ने समय से पूरा पैसा वापस लौटाने का और सरकार पर कोई आंच न आने देने का काम किया है।

श्री सीताराम येचुरीः सभापति महोदय, मैं आपसे पहले एक ही आश्वासन चाहता हूं कि आप बीच में नहीं टोकेंगे, यानी 12:00 बजे आप बंद न करने को कहें।

श्री सभापतिः आप हवाई जहाज की स्पीड से क्वेश्चन करिए।

श्री सीताराम येचुरीः सभापति जी, संक्षिप्त में पूछूंगा। पहली बात तो यह है कि सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सरकार नए एअरक्राफ्ट ला रही है। हमारी शिकायत यह रही है 16 साल की अवधि में, जब कि इन्हें नहीं लाया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये नए एअरक्राफ्ट जो आ रहे हैं, मीडिया ने देखा है कि उनके ऊपर हमने नाम लिखा है इंडियन, इन पर इंडियन एअरलाइन्स लिखा है, न एअर-इंडिया लिखा है, सिर्फ इंडियन लिखी है, तो क्या यह एक शुरूआता है कि आप इन दोनों कंपनियों का मर्जर करने जा रहा हैं और क्या इसलिए इन पर सिर्फ इंडियन लिखा गया है? मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री प्रफुल्ल पटेलः सर, इन कंपनीज का न एअर-इंडिया बदला गया है, न इंडियन एअरलाइन्स बदल गया है बल्कि यह इंडियन जो है, एक प्रकार से जैसे जैसे हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, मार्केट में वस्तु आ रही है, नई एअरलाइन्स आ रही है, कंपटीशन आ रही है, तो यह सब एक प्रकार से ब्रांडेड मार्केट स्ट्रेटजी है। It is a branding exercise or a marketing strategy. Now, you see, there is an aspirational change in India. Today, 35 years and below comprises 70 per cent of India. You see, how the private airlines are marketing. Tomorrow, you will also have to face the competition.

SHRI SITARAM YECHURY: But, are you considering the merger?

SHRI PRAFUL PATEL: No, merger is not on the cards as of now. We have discussed better synergies between the two carriers. We would also like to see that both of them can work closer in the best interest of the. ..*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: So, you are not ruling it out. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, the Minister definitely deserves the credit for taking a decision on a subject which had been pending for a long time. I would like to ask a slightly different question which he may not be able to answer today. There are Rs. 50,000 Crores that we are going to spend. Should he not try to see, in the negotiations, at least, some part of these aircrafts are manufactured in India? What is the domestic content? It may not be possible to manufacture these today. It should be possible over a period of time. What do you think about it?

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I can answer this question. In fact, we must be happy that though we are making such large purchases, we have got offsets which will be for goods or other services sourced from our country. And, that is to a very large extent. Normally, it is 30 per cent in the case of most of the transactions. But in the case of the Indian Airlines, our Finance Minister could get us even a better and a sweeter deal. We have got almost 40 per cent of offset in the Airbus negotiations. In the case of Air India, no final decision has yet been arrived at. But, 30 per cent is, in any way, the mandated offset. So, we will try to see that as much as possible of counter trade comes into the benefit of India. So, I think, at the end of the day, in spite of whatever the amount or volume, the net beneficiary will be the Indian trade and the Indian services.

श्री संजय राजाराम राउतः धन्यवाद, सभापति जी, मेरे प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य के प्रश्न से आ गया है।

PROF. P.J. KURIAN: Sir, what is the policy of the Government, if any State Government purchases aircraft or runs low-fair international flights?

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, the issue which the hon. Member has raised is, I am sure, regarding the Government's proposal. Sir, any Government is free to start an airline. But as far as international services are concerned, we have a policy that the more you fly within India, the more you connect India, the greater will be the reward.

PROF. P.J. KURIAN: You allow the private companies. Why don't you allow the State Government companies?

SHRI PRAFUL PATEL: What about Air India and Indian Airlines? Are they not Government companies? In fact, Air India and Indian Airlines have been given the exclusive rights for the next three years that they will be the only carriers flying to the Gulf. Whether it is the Kerala Government's

initiative or the Government of India's initiative, I think, it amounts to the same national interest and I appreciate it. I am sure, what you want is more connectivity from Kerala to the Gulf. We are ensuring it on a regular basis that the demand and supply ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Loans to SSIs and agricultural sectors by public sector banks

t*386. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the measures taken by Government to provide loans to small scale industries and agricultural sectors through public sector banks at cheap rate of interest;

(b) what is the percentage of rate of interest at which loans to these sectors are provided currently;

(c) what are the terms and conditions and time limit for loans without security; and

(d) details of loans sanctioned to small scale industrial units by banks during the past three years, State-wise?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM); (a) and (b) A policy was announced in June, 2004 envisaging doubling the flow of credit to agriculture from 2004-05 to 2006-07. Government has also announced a Policy Package which envisages doubling of credit flow from the public sector banks to the small and medium enterprises sector over the five years starting 2005-06. This policy would provide adequate enhancement of credit to SME sector.

As per the interest rate policy of Reserve Bank of India (RBI), interest rates on loans given by commercial banks have been deregulated. However, the interest rate on loans up to Rs. 2 lakh should not exceed the Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) of the banks concerned. BPLR is fixed taking into account *inter-alia,* their cost of funds, transaction cost and risk cost. Hence, the rate of interest on loans upto Rs. 2 lakhs is the barest minimum.

---

† Original notice of the Question was received in Hindi.